(b) if so, what are the details thereof?

(c) the estimated black money to be recovered thereby; and

(d) by when the schemes would be launched?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The Central Government has already launched schemes for mopping up black money which are in operation at present.

Checking tax evasion and unearthing black money is a continuous exercise and steps, as deemed necessary, are taken from time to time for this purpose.

(b) to (d) In view of replyto (a) above, do not arise.

सरकार के गैर-योजना व्यय में कटौती करने के लिए कदम

437. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "हैजी पिक्चर ऑन इनफ्लेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष उनके मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने सरकार के योजना भिन्न खर्च को कम करने के लिए, वर्तमान कर प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए तथा औद्योगिक संस्थाओं की उत्पादन क्षमता का इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस उपलब्धियां की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । "हैजी पिक्चर ऑन इनक्लेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार इंडियन एक्सप्रेस में 10 नवम्बर, 1991 को प्रकाशित हुआ था न कि 10 अक्तूबर, 1991 को ।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1991-92 के पहले छह महीनों के दौरान सितम्बर, 1991 तक (नवीनतम उपलब्ध) "खाद्य" समूह के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [आधार : 1990-91-100] में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

(ग) चालू वर्ष के बजट में ब्याज की अदायगियों को छोड़कर, आयोजनाभिन्न व्यय के लिए प्रावधान 4.9 प्रतिशत रखा गया है, जो 1990-91 (संशोधित अनुमान) में रखे गए प्रावधानों से कम है । सरकार द्वारा सरकार के योजनाभिन्न व्यय को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों में उर्वरकों तथा लेवी चीनी के लिए राजआर्थिक सहायता में कमी करना, निर्यातों के लिए नकद क्षतिपूर्ति समर्थन का उन्मूलन करना तथा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में 5 प्रतिशत की कमी करना (इसमें सांविधिक ब्लाक ऋण/राज्यों को अनुदान, पेंशन तथा ब्याज अदायगियां आदि शामिल नहीं हैं) शामिल है ।

(घ) सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न मुद्रास्फीति निरोधी उपायों के

[कारण मुद्रास्फिति की वार्षिक दर जैसा कि थोक मूल्य सूचकांक में आंकी गई है, बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर, 24 अगस्त, 1991 को 16.69 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर थी इसमें क्रम गिरावट दिखाई दी तथा 9 नवम्बर, 1991 को यह 13.51 प्रतिशत थी ।

Vacant Posts of Chairman and Director in Nationalised Banks

438. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. E. BALARAM:
DR. ABRAR AHMED:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Posts of Chairman and Directors of several nationalised banks are lying vacant for long time;

(b) if so, the details of such vacant posts, bank-wise and since what date;

(c) what are the reasons for delay in filling these vacancies and what steps are being taken in this regard;

(d) what are the details of directors appointed during the last three years from amongst the SCs/STs and backward communities; and

(e) what procedure is followed by Government in making these appointments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (e) The bank-wise position relating to vacancies of whole-time directors and non-official directors on the boards of the nationalised banks is given in the statement. (*See* below)

Of the total 10 vancancies of whole-time directors, 6 vacancies have arisen during 1991, 3 in 1990 and 1 in 1989. Most of the vacancies of non-official diretcors on the boards of nationalised banks have arisen in 1985. Government has already initiated necessary steps to fill up these vacancies.

At present, one non-official director belonging to SC/ST is in position on the boards of the following nationalised banks:—

1. Bank of India
2. Bank of Baroda
3. UCO Bank
4. Canara Bank
5. Union Bank of India
6. Allahabad Bank
7. Bank of Maharashtra
8. Andhra Bank
9. Corporation Bank
10. New Bank of India
11. Punjab and Sind Bank

Appointment of whole-time directors and non-official directors is made in accordance with the criteria and procedure prescribed in the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Schemes, 1970 and 1980. The above statutes provide for appointment of these directors after consultation with Reserve Bank of India.